वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा, राजस्थान में आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्वाटरों तथा कार्यालय के निर्माण संबंधी योजना कई वर्षों से सरकार के पास अनिर्णीत पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है और उस पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इस समय कार्यालय तथा रिहायशी मकानों के लिये प्रति वर्ष कितना किराया दिया जा रहा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) . आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभागों के एक संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण के लिए कोटा में 1955 में जमीन खरीदी गई थी। फिलहाल यह जमीन सैनिक अधिकारियों के वास्तविक कब्जे में है जिन्होंने इस जमीन के बारे में अपना दावा प्रस्तुत करके इस पर कब्जा कर लिया था। उनके कब्जे से जमीन को छुड़ाने की कार्यवाही पहले से ही जारी है। सैनिक अधिकारियों से जमीन छुट जाने के बाद ही कार्यालय भवन के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

(ग) कार्यालय स्थान के लिए 4,880 रुपये। सरकार द्वारा आवास देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

कृष्णा–गोदावरी नदी जल विवाद के बारे में न्यायाधिकरण

4153. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री वे० एच० पटेल :
श्री वे० मुहम्मद इमाम :

श्री सीताराम केसरी :
श्री मु० न० नाधनूर :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी के बंटवारे बन्धी विवाद को हल करने के लिए न्यायाधिकरण नियुक्त करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) न्यायाधिकरण कब तक नियुक्त किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) . इस विवाद को बातचीत द्वारा सुलझाने के लिए और प्रयत्न करने का विचार है और यदि इसमें सफलता न मिली तो इसे अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अधीन न्यायनिर्णय हेतु भेजने के लिए कार्यवाही करनी होगी।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण गृह निर्माण योजनाएं

4154. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4539 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश को ग्रामीण गृह निर्माण योजनाओं के लिए 1968–69 में कितनी धन राशि दी गई है ;